अंक 18, संख्या 4

अक्टूबर–दिसम्बर, 2018

जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का त्रैमासिक न्यूज़लैटर

क्षयरोग (टी.बी.) उन्मूलन एवं मातृ, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता हेतु अहमदाबाद (पश्चिम) के पार्षदों के लिए संवेदीकरण कार्याशाला

23 दिसम्बर, 2018, अहमदाबाद (पश्चिम), गुजरात

टी.बी. उन्मूलन एवं मातृ, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता हेतु अहमदाबाद (पश्चिम), गुजरात के पार्षदों के लिए एक संवेदीकरण कार्याशाला का आयोजन भारतीय संसदीय संस्थानः जनसख्ंया एवं विकास द्वारा 23 दिसम्बर, 2018 को किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन सत्र।

मुख्य अतिथियों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसख्ंया एवं विकास के कार्यकारी सचिव, श्री मनमोहन शर्मा ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला का उद्घाटन सांसद डा. किरीट पी. सोलंकी ने किया और अध्यक्षता अहमदाबाद नगर निगम की मेयर श्रीमती बिजल आर. पटेल द्वारा की गई।

कार्यशाला में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) विषय पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के संवेदीकरण के लिए एक प्रस्तुति डा. अभय कुमार, सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसख्ंया एवं विकास द्वारा की गई। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने गुजरात और भारत की तुलना करते हुए राज्य के स्वास्थ्य प्रोफाइल एवं अहमदाबाद का जनसांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों, एवं स्वास्थ्य और जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर केंद्रित थी।

इस अवसर पर चेतना (एक गैर सरकारी संस्था), अहमदाबाद की परियोजना निदेशक डा. स्मिता बाजपेयी द्वारा भी एक प्रस्तुति दी गई। साथ ही, डा. दीक्षित कपाड़िया ने क्षयरोग विषय पर एक प्रस्तुति दी।

कार्यशाला को उपस्थित पार्षदों ने बहुत सराहा। प्रतिभागियों ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य के अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्यशालाएं उन क्षेत्रों के पार्षदों के लाभ हेतु आयोजित की जानी चाहिए।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

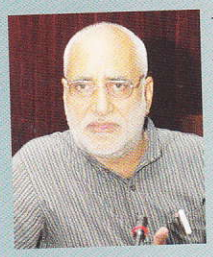

प्रधानमंत्री ने महिलाओं, बच्चों एवं किशोरों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए चौथे भागीदारी फोरम (Partners Forum) को आरम्भ किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य (PMNCH) की साझेदारी के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे भागीदार फोरम 2018 की मेजबानी नई दिल्ली में दिसम्बर 12–13 को की गई। इस फोरम का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों के लिए गति प्रदान करना था। पिछले भागीदारी फोरम दार–ए–सलाम, तंजानिया में सन् 2007 में, नई दिल्ली, भारत में सन् 2010 एवं जोहनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में सन् 2014 में, आयोजित किये गये थे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस फोरम का उद्घाटन दिसम्बर 12, 2018 को नई दिल्ली में किया गया।

दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आम चुनौतियों को संबोधित करने में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए, वैश्विक समुदाय ने भारत सरकार को इस साल के प्रतिष्ठित वैश्विक साझेदारों के फोरम की मेज़बानी सौंपी एवं सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की सन् 2013 तक प्राप्ति हेतु देश–स्तरीय कार्यवाही को और आगे बढ़ाने के लिए बातचीत के नेतृत्व करने का अवसर दिया।

इस सम्मेलन में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए चर्चा हेतु 85 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आमंत्रित देशों को सभी क्षेत्रों और आय स्तरों से चुना गया एवं इसमें वह देश भी सम्मलित थे जो वर्तमान में जी–7, जी–20, ब्रिक्स, आदि जैसे प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रिय निकायों की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह सम्मेलन वैश्विक उच्च–स्तरीय एवं बहु–देशीय (Multi Stakeholder Event) की श्रृंखला में चौथा था।

सम्मेलन में प्रस्तुत केस स्टडी के दौरान साझेदारी, क्रॉस–सेक्टोरल एक्शन, जवाबदेही और राजनीतिक नेतृत्व की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत से चुनी गई ऐसी ही एक सफलता की कहानी मिशन इंद्रधनुष है, जो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और 11 अन्य मंत्रालयों के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग है, जो 2020 तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच टीकाकरण कवरेज को 90 प्रतिशत तक बढ़ाएगा।

सम्मेलन ने प्रतिभागियों को यह बताने का भी अवसर प्रदान किया कि वह अन्य प्रतिभागियों के साथ अपने स्वास्थ्य विषयों को कवर करने के अनुभव साझा कर सकें और सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय एवं समाज के अन्य वर्गों के साथ बेहतर काम कैसे कर सकते हैं।

मनमोहन शर्मा
कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः
जनसंख्या एवं विकास

व्हाईट रिबन एलांयस इंटरनेश्नल के सी.ई.ओ. के साथ बैठक

7 दिसम्बर, 2018, नई दिल्ली

श्री बैट्सी मैक्कॉन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सुश्री आनंदा लिविंगस्टोन, एड्वोकेसी अधिकारी, व्हाईट रिबन एलांयस के साथ स्वास्थ्य से जुडे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक नई दिल्ली में 7 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार विमर्श एवं एलांयस द्वारा की गई वैश्विक पहलों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करना था।

बैठक के दौरान श्री मैक्कॉन ने एलांयस द्वारा अपनाई गई नई रणनीतियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने एलांयस की 20वीं वर्षगांठ की योजनाओं पर भी चर्चा की। एलांयस की राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अपराजिता गोगोई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बैठक के उद्देश्यों से अवगत कराया।

बैठक में श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसख्या एवं विकास ने भाग लिया।

पार्टनरस् फोरम 2018 के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा भारतीय संसदीय संस्थानः जनसख्या एवं विकास का दौरा

10–14 दिसम्बर, 2018

जाम्बिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, अल्बानिया, अजरबैजान और फ्लेमिश देशों के अंतर संसदीय मंच (ई.पी.एफ.) के आठ संसद सदस्यों ने भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का दौरा किया एवं भारतीय सांसदों एवं संस्थान के तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। अंतर संसदीय मंच के सदस्यों ने संबंधित देशों में हुए स्वास्थ्य सम्मेलनों और परिणामों के अनुभव भी साझा किए।

इस दौरे के अन्तर्गत प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने भारतीय विश्वविधालयों द्वारा प्रदान की जा रही यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को समझने के लिए हमदर्द विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविधालय की ओर से चलाए जा रहे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्लिनिक सुविधा का भी दौरा किया।

दौरे के एक भाग के रूप में 13 दिसम्बर, 2018 को भारतीय सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 7 भारतीय सांसदों सहित लगभग 19 सदस्यों ने भाग लिया। प्रो. पी.जे. कुरियन, पूर्व राज्यसभा उपाध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास के उपाध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हे भारत में स्वास्थ्य परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए सांसद डा. किरीट पी. सोलंकी द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई।

चर्चा के दौरान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारतीय सांसदों से चर्चा करते हुए।

संसदीय प्रतिनिधिमंडल सदस्यों एवं भारतीय सांसदों का ग्रुप चित्र।

फेफड़े के स्वास्थ्य (Lung Health) पर 50वां केंद्रीय विश्व सम्मेलन भारत में आरम्भ हुआ

21 नवंम्बर, 2018, नई दिल्ली

द यूनियन (The Union) की ओर से फेफड़े के स्वास्थ्य पर 50वें केंद्रीय विश्व सम्मेलन का शुभारम्भ 21 नवंम्बर, 2018 को नई दिल्ली में किया गया। इस विषय पर मुख्य सम्मेलन हैदराबाद, भारत में 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2019 के मध्य आयोजित किया जाएगा। क्षय रोग (T.B.) विषय पर संयुक्त राष्ट्र (UN) की पहली उच्च–स्तरीय बैठक और गैर–संचारी रोगों पर तीसरी उच्च–स्तरीय बैठक के एक साल बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय आपातकाल को समाप्त करना: विज्ञान, नेतृत्व एवं कार्य इस बात पर केंद्रित हैं कि प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चत करने के लिए क्या आवश्यक है, इन पर क्या कार्रवाही होती है एवं किस प्रकार यह जीवन बचाने के यह लक्ष्य पूरे होते हैं।

पिछले वर्ष एक करोड़ लोग क्षय रोग से बीमार हुए थे और 16 लाख लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। क्षय रोग एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य रोग है। इस के कारण एच.आई.वी./एड्स से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और इस प्रकार यह दुनिया का सबसे बड़ा संक्रामक रोगरुपी हत्यारा है।

द यूनियन के कार्यकारी निदेशक डा. जोस लुइस कास्त्रों ने इस अवसर पर कहा कि 'वैश्विक टी.बी. आपातकाल को समाप्त करने का समय आ गया है और इसका यह मतलब होगा कि सरकारें संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हस्ताक्षरित राजनीतिक घोषणा के अनुसार जवाबदेह होंगी। हैदराबाद में हमें यह देखना होगा कि हम ऐसे वास्तविक नेतृत्व को देख रहे हैं जो नैदानिक उपकरण, नई दवाओं और ज़मीन पर वैक्सीन और कार्रवाई दोनों में निवेश कर रहे हैं।

इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास (IAPPD) के कार्यकारी सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने भाग लिया।

सम्मेलन के मेज़बान देश के रूप में भारत दुनिया में टी.बी. के वर्तमान उच्चतम बोझ के साथ, जिस में इस रोग से ग्रस्ति प्रत्येक चार में से एक रोगी भारत में है, टी.बी. और फेफड़ों की बीमारी को समाप्त करने पर चर्चा के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। सन् 2017 में 2.74 मिलियन लोग टी.बी. से संक्रमित हुए एवं इसके कारण 4,21,000 लोगों की मृत्यु हुई। टी.बी. और मधुमेह की सह–संक्रमण की बढ़ती दर भी बहुत चिंता का कारण है। भारत सरकार ने 2025 तक टी.बी. को समाप्त करने का संकल्प लिया है।

सम्मेलन का विषय टी.बी. उन्मूलन हेतु दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है तथा यह जागरूकता भी बढ़ाता है कि फेफड़े के स्वास्थ्य के लिए टी.बी., वायु प्रदूषण, तंबाकू और बहुत कुछ ऐसे अन्य कारण एवं ऐसी आपात स्थिति हैं जिनसे बचने के लिए हमारे विज्ञान, नेतृत्व और इस दिशा में मिल कर कार्य करने की आवश्कता है।

फेफड़े के स्वास्थ्य पर 50वें केंद्रीय विश्व सम्मेलन का शुभारम्भ।

आई.सी.पी.डी. कार्यक्रम कार्यान्वयन (ICPD Programme of Action) विषय पर सांसदों का 7वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

22–23 अक्टूबर, 2018, ओटावा, कनाडा

70 से अधिक देशों के लगभग 90 सांसदों ने एक दूरंदेशी घोषणा (forward looking declaration) पर सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर वर्तमान राजनीतिक प्रवचन को संबोधित करने की तत्कालिकता के बारे में समझ और सहमति को बढ़ावा देना है। ओटावा में दो दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सांसदों ने जनसंख्या और विकास पर 1994 में हुए काहिरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया एवं इसकी सिफारिशों को लागू करने की दिशा में प्रगति पर चर्चा की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल अन्य प्रतिभागियों के साथ।

आई.सी.पी.डी. कार्यक्रम के कार्यान्वयन (ICPI) पर सांसदों का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनसंख्या और विकास समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है क्योंकि यह अगले वर्ष आई.सी.पी.डी. की 25वीं वर्षगांठ का पुर्न–निरिक्षण करने का समय है।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कनाडाई एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियनस् ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (CAPPD), इंटर–अमेरिकन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (AIPG), यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (UNFPA), ग्लोबल अफेयर्स कनाडा (GAC), जनसंख्या और विकास पर यूरोपीय संसदीय मंच (EPF) और यौन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए एक्शन कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, श्री किरीट पी. सोलंकी, सांसद एवं श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

प्रतिबद्धता हेतु सहमति के ओटावा घोषणापत्र में, सांसदों ने एक ऐसे विश्व की स्थापना की शपथ ली जहाँ बचाई जा सकने वाली मातृ मृत्यु अतीत की बात हो, जहाँ परिवार नियोजन के लिए आवश्यकता पूरी हो, जहाँ लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाएं मौजूद नहीं हों, जहाँ युवा लोग स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें, जहाँ समाज में कलंक और भेदभाव का कोई स्थान नहीं हो और जहाँ प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए एवं उनकी रक्षा की जाए।

सभी माताओं और नवजात शिशुओं

महिलाओं की सकारात्मक गर्भावस्था अ
सम्मानजनक मातृत्व देखभाल और जन्म के समय

केंद्रीय स्वास्थ्य

सुश्री अनुप्रिया पटेल
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

स्वास्थ्य देखभाल केवल बीमारी के इलाज के बारे में नहीं है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति को बढ़ावा देने के बारे में है। इसके लिए एक व्यापक दृश्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्भावस्था और बचपन से लेकर किशोरावस्था और अंत में वयस्कता तक देखभाल की निरंतरता होती है। यह लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों कि यह वर्ग अक्सर उपेक्षित रहता है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अपनी माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है। सन् 2000 और 2015 के मध्य, भारत की मातृ मृत्यु दर में सन् 2000 में 1 लाख जीवित जन्मों में प्रति वर्ष 556 से 77 प्रतिशत की गिरावट आई जोकि 2015 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में 130 हो गई। इसी अवधि के दौरान, भारत की नवजात मृत्यु दर 1.2 मिलियन नवजात मृत्यु से 44 प्रतिशत कम हो गई (सालाना 7 लाख से कम)। फिर भी हमें सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्ति करने एवं इस दिशा में आगे बढ़ने हेतु एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत मातृ मृत्यु दर अनुपात को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम और नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति हजार जीवित जन्मों पर सन् 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों के तहत कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास गर्भाधान और प्रसव के समय से पहले शुरू होते हैं। किशोरावस्था जबरदस्त विकास का समय है, और, दुर्भाग्यवश, लड़कियाँ पोषण संबंधी कमियों के साथ मातृ अवस्था में प्रवेश करती हैं जो उनको गर्भधारण को जोखिम में डालती हैं। 2016 में, हमारे देश में किशोरावस्था प्राप्त आधी से अधिक लड़कियां रक्ताल्पता (एनीमिक) से ग्रस्त थीं। भारत सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं में किशोरियों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराना है। हमारे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में, पाँच प्रमुख क्षेत्रों में किशोरों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को व्यापक रूप से संबोधित करने की रणनीति के हिस्से के रूप में, पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, दिल्ली में आयोजित मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य भागीधारी फोरम के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

समान स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए

व के अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए
साथी की उपस्थित महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक हैं।

पटेल
र कल्याण राज्य मंत्री
कार

हमारी हालिया सफलता के लिए इस तथ्य को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि पहले से कहीं अधिक महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपनी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल कराना चाहती हैं। 2016 में लॉन्च किया गया प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सभी गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव देखभाल सुनिश्चित करता है। ऐसी अन्य अनेक योजनाएं भी हैं जो विशेष रूप से अधिक से अधिक महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इन प्रयासों के कारण, अधिक संख्या में महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रसव हेतु चुन रही हैं, जिसका पहले उनके घर में विरोध होता था, यह उन्हें कुशल देखभाल का उपयोग करने की अनुमति देते है एवं यह दुनिया में शिशुओं को सुरक्षित रूप से लाने के लिए आवश्यक है। सन् 2015–16 के दौरान, 79 प्रतिशत महिलाओं ने स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव किया, जबकि 2005–06 में केवल 39 प्रतिशत महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।

फिर भी केवल देखभाल की पहुंच सकारात्मक परिणाम की गारंटी नहीं देती है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ दी जानी चाहिए। उच्च प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो सरकार द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं, गर्भावस्था की जटिलताओं और मृतजन्म (स्टिलबर्थ) के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए लेबररूम प्रथाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और इन्हें मज़बूत करने के लिए अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं। सम्मान. जनक मातृत्व देखभाल और जन्म के समय जीवनसाथी, इन प्रयासों की अन्य महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं को एक सकारात्मक गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव प्राप्त हो।

एक बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे गर्म, पोषित और संक्रमण (warm, nourished and protected) से सुरक्षित हैं। आमतौर पर स्वास्थ्य सुविधा में जन्म के तुरंत बाद माताओं और शिशुओं के लिए प्रसवोत्तर देखभाल शुरू हो जाती है।

यह देखभाल की निरंतरता में एक महत्वपूर्ण और अक्सर उपेक्षित बिंदु है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद बीमारी और बच्चों की मृत्यु का खतरा सबसे अधिक होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस ओर अधिक फोकस की आवश्यकता है कि हर मां और नवजात शिशु के जीवन के पहले कुछ दिनों और हफ्तों में उनकी देखभाल के लिए जीवन रक्षक हस्तक्षेप (life saving interventions) उनके घर तक पहुंच जाएं। बेशक, जैसे–जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कई अन्य हस्तक्षेप प्रदान किए जाते हैं, जिसमें टीकाकरण और माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लिमेंटेशन जैसे विटामिन ए, आदि शामिल हैं।

दिसंबर 2018 में, भारत सरकार ने दिल्ली में मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य (PMNCH) भागीधारी फोरम (Partners Forum) के लिए साझेदारी की मेज़बानी की। इसने इस क्षेत्र में हमारी सफलताओं को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान किया एवं हमारी महिलाआ. और बच्चों के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता को भी प्रतिबिंबित किया। हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को एक वास्तविकता बनाना चाहिए क्योंकि वित्तीय बाधाओं के डर के बिना सभी को स्वास्थ्य का अधिकार है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य देखभाल उच्च गुणवत्ता की हो, सभी के लिए समान हो और उन्हें गरिमा प्रदान करे। हमें स्वीकार करना चाहिए कि स्वास्थ्य देखभाल एक निरंतर प्रक्रिया है, यह न केवल उपचार को पहचानती है, बल्कि रोकथाम, स्वस्थ व्यवहारों और स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को भी दर्शाती है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों तक सही प्रकार से पहुँचे यह हमारा उत्तरदायित्व है।

स्रोतः हिंदुस्तान टाइम्स, 18 दिसंबर, 2018।

युवावस्था में निवेशः

सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के क्षेत्रीय विकास और उपलब्धि की ओर जनसंख्या और विकास भाग-2 पर एशियाई और अरब सांसदों की बैठक एवं अध्ययन दौरा

2–3 अक्टूबर, 2018, मनामा, द किंगडम ऑफ बहरीन

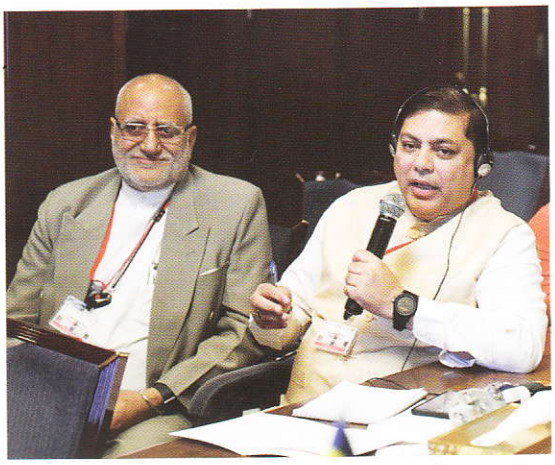

श्री नदिमुल हक, सांसद, (दाये) एवं श्री मनमोहन शर्मा, बैठक में भाग लेते हुए।

एशियन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (APDA), जो कि जापान के सांसदों के फेडरेशन फॉर पॉपुलेशन (JPFP) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ने बहरीन शूरा काउंसिल के साथ मिलकर जनसंख्या और विकास भाग–2 पर एशियाई और अरब सांसदों की बैठक और अध्ययन दौरे का आयोजन, 2–3 अक्टूबर, 2018 के मध्य मनामा, बहरीन साम्राज्य में किया गया। यह सम्मेलन जापान ट्रस्ट फंड (JTF), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), और इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन (IPPF) के सहयोग से अरब और एशिया क्षेत्रों में जनसंख्या और विकास पर संसदीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर–क्षेत्रीय सहयोगात्मक परियोजना के भाग के रूप में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन में लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 17 एशिया और अरब देशों के सांसदों, संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र की कंपनियाँ और शिक्षाविद शामिल थे। भारत से, श्री नदिमुल हक, सांसद, श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, और श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

पिछले साल जॉर्डन में परियोजना के भाग–1 के दौरान यह सहमति बनी थी कि सांस्कृतिक मूल्यों पर बहस को अलग रखने और इसके बजाय भाग लेने वाले देशों में से प्रत्येक के लिए स्वीकार्य तरीके से जनसंख्या के मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थायी विकास के लिए शर्तों को स्थापित करने की आवश्यकता है। बहरीन सम्मेलन का उद्देश्य पिछले वर्ष की परियोजना के विषय पर अनुवर्ती था, जिसमें अरब क्षेत्र में युवाओं की आबादी

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

को सामाजिक अस्थिरता का स्रोत बनाने के स्थान पर स्थायी विकास के लिए एक इंजन के रूप में उपयोग करने के लिए ठोस तरीकों पर चर्चा करने पर बल दिया गया था। जनसांख्यिकीय संक्रमण के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में युवाओं की आबादी तेजी से बढ़ रही है।

सहभागिता का स्वागत करते हुए, माननीय तेरूहिको माशिको (JPFP के उपाध्यक्ष और APDA के निदेशक), ने JPFP और APDA की ओर से इस सम्मेलन की मूल अवधारणा को बताया और जनसंख्या और विकास पर संसदीय गतिविधियों के अंतर्निहित सिद्धांतों और महत्व की पुष्टि की।

भारत के सांसद, श्री नदिमुल हक ने जनसंख्या और एस.डी.जी. विषय पर एक प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने बताया कि किसी भी विकास का लक्ष्य लोगों के लिए कल्याण और बेहतर रहने की स्थिति है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है और साथ ही यह शहरीकरण, प्रवासन, अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, आदि को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय स्थिरता को खतरे में डालती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देशों को अधिकार आधारित और लैंगिक संवेदनशील नीतियों को अपनाकर लोगों की पसंद, संसाधनशीलता, रचनात्मकता और लचीलापन बढ़ाने का काम करना चाहिए।

क्षेत्रीय विकास के लिए सांसदों की भूमिका पर सत्र के दौरान यह रेखांकित किया गया कि देश के नागरिकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन (TAGG) सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दे सकते हैं।

अंतिम सत्र में, सांसदों के वक्तव्य को अपनाने के लिए चर्चा हुई। सांसदों ने निम्नलिखित के लिए एक स्पष्ट बयान अपनाया:

1. युवाओं के लिए उचित शिक्षा और रोज़गार के अवसर पैदा करना विकास के लिए पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करेंगे,
2. एस.डी.जी. की प्राप्ति और आबादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए,

श्री नदिमुल हक, सांसद, एस.डी.जी. विषय पर प्रस्तुति देते हुए।

बीमारियों को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मृत्यु दर को बढ़ावा देने के प्रयासों की आवश्यकता है और प्रजनन संक्रमण में तुलनीय प्रयासों को भी किया जाना चाहिए,

3. विशेष रूप से, अवांछित गर्भधारण को समाप्त करना सर्वोपरि महत्व है,
4. इसके लिए प्रत्येक आयु वर्ग के लिए चिकित्सा ज्ञान पर स्थापित कामुकता शिक्षा (sexuality education) और परिवार नियोजन सहित प्रजनन स्वास्थ्य (आर.एच.) सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता होती है, तथा
5. कानून के माध्यम से इस बारे में अनुकूल माहौल बनाने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अध्ययन दौरे के अन्तर्गत प्रतिभागियों ने बहरीन शिक्षा मंत्रालय का दौरा किया, जहां उन्हें बहरीन में शिक्षा की स्थिति और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बताया गया, जिसके बाद एक सक्रिय प्रश्न और उत्तर सत्र हुआ। प्रतिभागियों ने बहरीन विज्ञान केंद्र का भी दौरा किया, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केन्द्र है। यह केन्द्र बहरीन युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की देखरेख में सतत् विकास लक्ष्यों को समर्पित है। ब्रीफिंग के बाद, उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने में सरकारी प्रयासों को जानने में प्रतिभागियों की विशेष रुचि थी।

प्रतिभागी सत्र के दौरान चर्चा करते हुए।

"लीविंग नो वन बिहाइंड"

युवाओं में निवेश विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अस्ताना, कजाकिस्तान, 19–20 अक्टूबर, 2018

कजाकिस्तान गणराज्य की संसद, कजाकिस्तान गणराज्य के सामाजिक विकास मंत्रालय, और एशियाई जनसंख्या और विकास संघ (APDA) द्वारा अस्ताना, कजाकिस्तान में युवाओं में निवेश विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 19–20, 2018 के मध्य किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने जापान ट्रस्ट फंड (JTF) के माध्यम से सम्मेलन का समर्थन किया।

सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य एक शांतिपूर्ण, समावेशी, टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत समाज के निर्माण के लिए आज के युवाओं में निवेश के महत्व को दर्शाना था। सांसदों, मंत्रियों, विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों, एशिया–प्रशांत क्षेत्र के अरब, अफ्रीका और यूरोप के 35 देशों के कुल 200 प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

भारत से, श्री हुसैन दलवई, सांसद, और श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, और भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास के कार्यकारी सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में, कजाकिस्तान गणराज्य की संसद के मजलिस के अध्यक्ष माननीय नूरलान निगमातुलिन ने स्वागत भाषण दिया, इसके बाद श्री फुकुदा ने बताया कि जापान द्वारा शिक्षा में व्यापक निवेश के परिणामस्वरूप, जिसमें प्राकृतिक संसाधन सीमित थे, जापान के विकास की नींव तैयार हुई। उन्होंने कहा, "हम सभी एक समय युवा थे। हमारी आकांक्षाएं और सपने थे, लेकिन हमने विभिन्न कठिनाइयों का भी अनुभव किया। यह बहुत अच्छा होता यदि हम अपनी युवावस्था में लौट सकते, लेकिन चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए यह हमारा मिशन है कि हम सक्रिय रूप से निवेश करें और युवा लोगों का समर्थन करें ताकि उन्हें उतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जितनी हमने कीं"।

सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चार महत्वपूर्ण सत्र शामिल किये गयेः

1. युवाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और परस्पर जुड़ाव और बदलाव में सुधार करना।
2. स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार।
3. नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में युवाओं की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना।
4. भूमंडलीकरण के संदर्भ में युवाओं के लिए अवसर और जोखिम।

प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि युवा लोगों को एक ऐसी दुनिया विरासत में मिल रही है, जहां वैशिवक जलवायु हमारी आशा से अधिक तेज़ी से बदल रही है। परन्तु युवाओं में एक मजबूत सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता है, जो भविष्य में समाजों को निम्न कार्बन और जलवायु को परिवर्तनाशील बनाने की ताकत रखती है। सम्मेलन ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास गतिविधियों और युवा उद्यमियों, छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच परस्पर संवाद के माध्यम से कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान देने पर सहमति व्यक्त की।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

मेदांता टीबी कॉनक्लेव 2018

टी.बी. मुक्त भारत के लिए बहु-क्षेत्रीय भागीदारी पर राष्ट्रीय परामर्श

26 नवंबर, 2018, नई दिल्ली

मेडसिटी, तपेदिक और फेफड़ों की बीमारी के अन्तर्राष्ट्रीय संघ (The Union) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने साथ मिलकर एक दिन के सम्मेलन को टीबी–मुक्त कार्रवाई के लिए एक कॉल के रूप में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में डीडीजी, सीटीडी (डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल टीबी डिवीजन), डीएचएस (डायरेक्टर हेल्थ सर्विस – टीबी) हरियाणा, और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) सहित सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास के कार्यकारी सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

कान्क्लेव का उद्घाटन सत्र।

सम्मेलन में भारत में टी.बी. निदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना और 2025 तक टी.बी. मुक्त भारत के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ–साथ इस सामयिक मुद्दे पर कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

टेलिंग नम्बरस् (TELLING NUMBERS)

आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में जनसंख्या गिर रही है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू सन् 2015 के बाद से लोगों को यह सुनिश्चित करने और अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनका राज्य जापान की तरह जनसांख्यिकीय संकट न झेले, और राज्य में पर्याप्त युवा आबादी बनी रहे। उन्होंने हाल ही में, 28 दिसंबर, 2018 को अपने इस आवाहन को दोहराया।

आंध्र प्रदेश उन कई भारतीय राज्यों में से है, जहां प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। श्री अश्विन कुमार चौबे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (एनएफएचएस–4) (2015–16) के आँकडे लोक सभा में प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि भारत में समग्र प्रजनन दर 2.18 है।

भारत की कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) एनएफएचएस–1 (1992–93) में 3.39 थी। एनएफएचएस–4 (2015–16) में 1.83 से आगे बढ़ने से पहले आंध्र प्रदेश के लिए टी.एफ.आर. एनएफएचएस–1 में 2.29 से एन.एच.एफ.डब्ल्यू.–2 में 2.25 (1998–99) और एन.एफ.एच.एस.–3 (2005–06) में 1.79 गिर गयी। डेटा के अनुसार बिहार (3.4) और उत्तर प्रदेश (2.74) में टी.एफ.आर. बडे राज्यों में सबसे अधिक है।

टी.एफ.आर. उन बच्चों की संख्या है जो एक महिला के जीवनकाल में जन्म लेने या होने की संभावना रखते हैं। टी.एफ.आर. 2.1 को प्रतिस्थापन–स्तर की उर्वरता (replacement level fertility) के रूप में देखा जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रैस, 7.1.2019।

भारत की जनसंख्या में 1 जनवरी, 2019 को 69,000 से अधिक शिशु जुडे

दुर्गेश नंदन झा

यूनिसेफ द्वारा जारी आंकडों के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक भारत में 69,944 शिशु नए साल के दिन जनसंख्या में जुडे। इसके बाद, प्रत्येक दिन दुनिया भर के विभिन्न देशों में कुल जन्म लेने वाले शिशुओं में से चीन (44,940), नाइजीरिया (25,685), पाकिस्तान (15,112) और इंडोनेशिया (13,256) ने शिशुओं का स्वागत किया। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में पैदा हुए 3,95,072 शिशुओं में से 18 प्रतिशत भारत में पैदा हुए हैं।

डॉ यास्मीन अली हक, भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि, ने टाईम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कई नवजात शिशु स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण एक वर्ष या एक दिन भी जीवित नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस नए साल के दिन, हमें प्रसव या संक्रमण के दौरान जटिल. ताओं के कारण पैदा हुए प्रत्येक बच्चे को रुग्णता या मृत्यु से बचाने का संकल्प करना चाहिए, ।

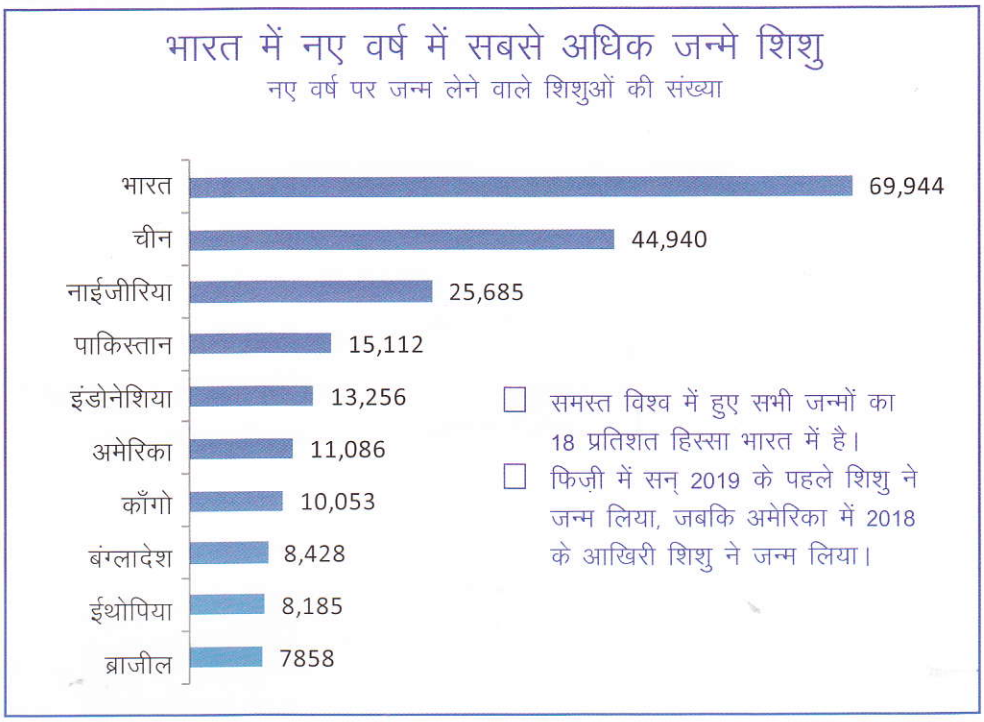

2017 में, जन्म के दिन ही लगभग 1 करोड बच्चों की मृत्यु हुई, और सिर्फ उनके जन्म के पहले महीने में 25 लाख बच्चों की मृत्यु हुई। जबकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी शिशु मृत्यु दर में काफी सुधार किया है। हक ने कहा कि नवजात मृत्यु दर को कम करना एक चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई नवजात मौतों को साधारण सुधारों के साथ रोका जा सकता है जैसे कि विशेष स्तनपान, माँ या पिता और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क, दवाओं और आवश्यक उपकरणों और कुशल स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा साफ एवं अच्छी तरह से सुसज्जित स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच।

स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 जनवरी 2019।

जनसंदेश
संपादक
मनमोहन शर्मा
जनसंदेश एक त्रैमासिक पत्रिका है

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास
(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शदाता स्थिति)
1/6, सीरा इन्स्टीटयूशनल एरिया, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली–110049
दूरभाषः 011–4165661/67/68/76, फैक्सः 011–41656660
ई.मेल: iappd@airtelmail.in, वेब साईट: www.iappd.org

Asha Enterprises: 9811854631